



1. डॉ० किशोर कुमार
2. शेखर कुमार

जीविका दीदियों के कार्यों का विस्तार (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

1. सहायक प्राध्यापक, 2. शोध अध्येता- समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत

Received-16.02.2023, Revised-23.02.2023, Accepted-27.02.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सांशः स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं की सीमबद्धताओं के कारण केन्द्र सरकार ने उनका पुनर्गठन राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के बतौर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कुशल-अकुशल लोगों को सामुदायिक समूहों में संगठित करके उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी के वर्तमान स्तर से उन्हें ऊपर उठाना है। कार्यक्रम के चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी के जीविका मॉडल का कार्य विस्तार करते हुए सोसाइटी को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंग के बतौर बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन में तब्दील कर दिया। फलतः प्रथम चरण में 2012-13 में सोसाइटी का काम पहले जिन छः जिलों में चल रहा था, उनके सभी प्रखण्डों में 12 नए जिलों के तीन-तीन प्रखण्डों में और 17 जिलों के एक-एक प्रखण्ड में शुरू किया गया। शेष प्रखण्डों को कार्यक्रम में चरणबद्ध ढंग से 2013-14 में शामिल किया गया।

कुंजीभूत शब्द- स्वरोजगार, पुनर्गठन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका, ग्रामीण क्षेत्र, सामुदायिक समूहों, वर्तमान स्तर, संगठनों।

इस कार्यक्रम के तहत 1.50 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65 हजार ग्राम संगठनों, 16 हजार संकुल स्तरीय संघों और 534 प्रखण्ड स्तरीय संघों में संगठित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 3 लाख सामुदायिक पैरा-पेशावरों और 75 हजार सामुदायिक साधन सेवियों के चिन्हित तथा प्रशिक्षित किया गया है। इन परिवारों की कुल बचत राशि लगभग 3,100 करोड़ तक पहुँचने की आशा है। वे लोग सामुदायिक निवेश निधि से 5,800 करोड़ रुपये और बैंकों से 12,000 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

अभी तक 12 लाख गरीब परिवारों को शामिल करते हुए 99.5 हजार स्वयं सहायता समूह, 10.6 हजार ग्राम संगठन और 73 संकुल स्तरीय संघ संगठित हुए हैं। 66 हजार पूर्व गठित स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खुले हैं और 50.8 हजार समूहों का बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। इसके अतिरिक्त समूह को बैंकों से 196.8 करोड़ ऋण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 3.8 हजार ग्राम संगठनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है और लगभग 3 हजार ग्राम संगठनों को स्वास्थ्य सुरक्षा कोष उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए 1.38 लाख परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और 1.46 लाख परिवारों को जन सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित कराया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2.14 लाख किसानों को विभिन्न आधुनिक फसल तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाया गया है और पशुपालन में उत्पादन वृद्धि के लिए 10.5 हजार दूध उत्पादकों को 269 दुग्ध सहकारी समितियों में संगठित किया गया है।

कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की बचत की आदत विकसित होगी और उनके लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। यह नारी सशक्तिकरण का भी एक माध्यम होगा। पारम्परिक कलाओं और शिल्पों, अगरबत्ती, शहद आदि की मूल्य श्रृंखला हेतु अवसर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

वर्तमान समय में जीविका दीदियों के कार्यों का विस्तार किया गया है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में 'मे आई हेल्प यू डेस्क' जीविका दीदी संभालेंगे। वे अस्पताल आने वाले मरीजों को स्थानीय भाषा में अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देगी।

जीविका दीदी स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध होगी, इसलिए स्थानीय लोगों से उनका परिचय, उनके आचार-व्यवहार एवं जीवनशैली से परिचित होगी। वे हरेज मरीज को अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में मदद करेगी। कहीं डॉक्टर मिलेंगे और कहीं जाँच होगी, दवाएँ कैसे उपलब्ध होंगी, इसकी जानकारी 'मे आई हेल्प यू डेस्क' से मरीज एवं उनके परिजनों को आसानी से मिल जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जीविका समूह से संबद्ध जीविका दीदी को अस्पताल के कार्यों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को जीविका द्वारा चयनित जीविका दीदी को 'मे आई हेल्प यू डेस्क' की जिम्मेदारी सौंपे जाने के पूर्व उन्हें जिला अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम जीविका के स्तर से तय किया जायेगा। वही स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रबन्धन से जुड़े पदाधिकारी जीविका दीदियों को प्रशिक्षण देंगे।



जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 'मे आई हेल्प यू डेस्क' बनाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षकों को 'मे आई हेल्प यू डेस्क' के लिए अस्पताल परिसर में ऐसे स्थान पर 'मे आई हेल्प यू डेस्क' होगा, जहाँ से मरीजों का आवागमन सामान्य रूप से होता है।

जीविका दीदियों करेंगी अस्पतालों में कपड़ों की आपूर्ति एवं सफाई- बिहार के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई जीविका दीदी करेंगी। इसके साथ ही साथ जिला अस्पतालों में एवं अनुमंडल अस्पतालों में कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था भी जीविका दीदी के हाथों में होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह बैठक 27 जनवरी, 2023 को हुई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के ऊपर मुख्य सचिव डॉ० एसों सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस कार्य में प्रति मरीज खर्च का आंकलन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा निर्धारित की गई दर को आधार मानकर किया जाएगा। पोशाक तैयार करने के लिए बुनकरों से कपड़े की खरीद के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड तथा धुलाई एवं अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जीविका के साथ अनुबंध किया जाएगा। वहीं जीविका द्वारा सभी अस्पतालों में साफ-सफाई अनिवार्य रूप से सातों दिन चक्रीय रूप से 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान समय में राज्य के सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों के भर्ती मरीजों को उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था दीदी की रसोई से कराई जा रही है।

जीविका दीदियों ने कोरोना में शानदार काम किया- कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एकजुट कर जीविका दीदियों ने आम लोगों को इससे जागरूक किया। मास्क बनाने तथा उपलब्ध करवाने में अहम योगदान दिया। कोविड के समय क्राइसिस मैनेजमेंट की मिसाल कायम की। कोविड-19 से लड़ने के दोनों प्रमुख हथियार मास्क और सेनेटाइजर बनाकर लोगों की मदद की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी है जिनमें 88 प्रतिशत सम्पूर्ण महिला एसएचजी है। समूह सहायता समूह की जीविका दीदी ने बिहार सहित पूरे देश में आर्थिक और सामाजिक क्रांति कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी लकीर खींची है। केन्द्र और राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और कोविड के समय मास्क की आपूर्ति जैसी सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रमों की सफलता में जीविका की दीदीयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बन चुकी है। सर्विस सेक्टर में बैंक सखी, सीएसपी का संचालन और राज्य के अस्पतालों की कैंटीन भी जीविका दीदी चला रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि जीविका दीदी पैसे को संभालने, वित्तीय निर्णय लेने और बेहतर सामाजिक नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम बनकर उभरी हैं तथा इस भूमिका में काम कर रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, डॉ० नवीन, : सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूह की भूमिका, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, 2015.
2. हिन्दुस्तान, पटना, 09 मार्च, 2022.
3. हिन्दुस्तान, पटना, 03 नवम्बर, 2023.
4. हिन्दुस्तान, पटना, 28 जनवरी, 2023.
5. हिन्दुस्तान, पटना, 01 फरवरी, 2023.
6. हिन्दुस्तान, पटना, 29 जनवरी, 2023.
7. हिन्दुस्तान, पटना, 30 जनवरी, 2023.
8. हिन्दुस्तान, पटना, 31 जनवरी, 2023.
